

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3869
दिनांक 11.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीलंका के साथ समझौते

3869. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री और हवाई संपर्क, पर्यटन, व्यापार और उच्च शिक्षा में आपसी सहयोग संबंधी समझौतों पर भी विचार-विमर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संविधान के 13 वें संशोधन के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी तथा यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और घरों के निर्माण सहित विस्थापित श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास का आश्वासन देने वाले विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ किन्हीं द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत द्वारा श्रीलंका को दिवालियापन से बचाने के लिए अब तक प्रदान की गई वित्तीय और मानवीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री रानिल विक्रमसिंघे ने 20-21 जुलाई 2023 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय विचार-विमर्श किया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यात्रा के दौरान एक विजन स्टेटमेंट जारी किया गया जिसका शीर्षक था "संपर्क को बढ़ावा देना, समृद्धि को उत्प्रेरित करना: भारत-श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन"। प्रधानमंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं और तेरहवें संशोधन को लागू करने तथा प्रांतीय परिषद चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी।

यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान-प्रदान किया गया।

- (1) नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;
- (2) श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में आर्थिक विकास पहल पर सहयोग ज्ञापन,
- (3) पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में संयुक्त आशय घोषणा,
- (4) श्रीलंका में यूपीआई स्वीकृति के लिए एनआईपीएल और लंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क करार।

(ड) सरकार अपनी 'पड़ोस प्रथम' नीति के तहत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के प्रतिउत्तर में, फरवरी 2022 में भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक नई ऋण सहायता (एलओसी) प्रदान की थी। मार्च 2022 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की गई थी। भारत ने जनवरी 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय और 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एशियन क्लियरिंग यूनियन और सार्क स्वैप का विलंबित बकाया प्रदान किया। दवाओं की भारी कमी को पूरा करने के लिए अप्रैल-मई 2022 में पेरुडेनिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जाफना टीचिंग हॉस्पिटल, हंबनटोटा जनरल हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सर्विस '1990' को 26 टन से अधिक दवाएं तथा अन्य चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की गई। इसके अलावा, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मछुआरों की आजीविका को बहाल करने के लिए केरोसिन की एक खेप वितरित की गई। जून 2022 में यूरिया उर्वरक के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की गई थी। प्राप्तकर्ता परिवारों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने उत्तरी प्रांत के चार जिलों में मछुआरा समुदायों के साथ-साथ श्रीलंका के अन्य हिस्से जैसे पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी प्रान्तों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच जरूरत के हिसाब से तैयार सूखा राशन वितरित किया।
